राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता
1.	2123/2023	पूर्णराम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), जयपुर राजस्थान। 3. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर। 4. पुलिस अधीक्षक, सीकर, राजस्थान।	श्री मुकेश बिजारणियां
2.	2124/2023	अनिल कुमार		

आदेश की दिनांक : 21.08.2023

उपस्थित :–
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2123/2023 पूर्णराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, (गृह विभाग) के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कॉस्टेबल के पद पर 1995 में हुई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति हैड कॉस्टेबल के पद पर वर्ष 2016 में हुई। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 04.08.2023 के द्वारा सीकर जिले से आयुक्तालय, जयपुर में रेंज आवंटित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि सीकर रेंज व जयपुर रेंज दोनों अलग अलग रेंज है। ऐसे में अपीलार्थी का रेंज परिवर्तन किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि हैड कांस्टेबल पद की वरिष्ठता रेंज स्तर पर निर्धारित होती है। ऐसे में रेंज परिवर्तन किये जाने से वरिष्ठता विपरीत रूप से प्रभावित होगी। उनका यह भी तर्क है कि हैड कांस्टेबल के रेंज से बाहर पदस्थापन को माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 10353/2021 सुभाष चन्द्र

बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 में उचित नहीं माना है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी पूर्व में निलम्बित था और प्रत्यर्थी विभाग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजिकृत आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित पुलिस कर्मियों का बहाल किये जाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किया गया है और बहाली के उपरान्त अपीलार्थी को रेंज आवंटित किया गया है, जो उनके विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन मामले को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. आलोच्य आदेश दिनांक 04.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सीकर जिले से आयुक्तालय, जयपुर में रेंज आवंटित किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश से अपीलार्थी का रेंज परिवर्तन किया जाना प्रकट होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10353/2021 सुभाष चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> (32) This Court is of the firm view that in the face of substantive provision, namely, Rule 26 of the Rules of 1989, which provides that seniority of Constable and Head-Constable shall be maintained district-wise and the seniority of Assistant Sub-Inspector will be maintained range-wise, no administrative order much less order dated 10.08.2021, issued by the Director General of Police, can protect or affect their seniority. Petitioners' seniority cannot be maintained de-hors Rule 26 of the Rules of 1989.
>
> (33) This Court has consistently held that inter-district transfers of Constables and Head-Constables and inter-range transfers of ASI's are contrary to Rule 26 of the Rules of 1989. It will not be out of place to reproduce adjudication made by this Court in the case of Smt. Premlata (supra), which reads thus:-
>
> "A perusal of the said Rules shows that the persons mentioned in column 5 of Sections I, II and IV of the Schedule-I holding substantive rank shall be eligible in the case of Constables on District/Unit, Battalion basis, which means that the concerned Constable shall be promoted as and when his/her turn comes in the district to which he/she has been transferred. Mr. Jai Singh, Dy. Superintendent of Police, Traffic, Bikaner is present in the Court and confirms the said fact. Thus, this Court fails to understand as to how the petitioner does not stand to suffer, in case she is transferred from Bikaner to Jhunjhunu because, even though, the seniority is maintained from the date of the appointment, she will be promoted only in case the person senior to her in Jhunjhunu has been promoted though his initial appointment is after the date of the initial appointment of the present petitioner. Thus, the transfer order which places the petitioner in disadvantage vis-a-vis for the purpose of promotion cannot be sustained."
>
> (34) Coordinate Benches of this Court have followed the aforesaid view in the cases of Yadram (supra) and Harendra(supra).
>
> (35) As the appointing authority of Constable/Head-Constable is the Superintendent of Police of the district concerned, consequent to their

transfer under consideration, the Constables and Head-Constables will be required to receive instructions/directions from the Superintendent of Police of the district in which they have been transferred and as a natural corollary of their transfer, their appointing authority, so also the disciplinary authority will be changed.

(36) Such action of the respondents cannot be countenanced as the Appointing Authority and Disciplinary Authority of an employee cannot be changed without his/her consent.

(37) The transfers made vide order under challenge are, on the one hand, contrary to the statutory provisions and judgments of this Court and on the other hand reflective of non-application of mind.

(38) This Court fails to comprehend that if any disciplinary action is to be taken against a transferred Constable/Head- Constable, then, who will be the competent authority to initiate the enquiry? Subhash Chandra (petitioner in S.B. Civil Writ Petition No.10353/2021), being a Constable (General Duty), has been transferred from Jaisalmer to G.R.P., Ajmer; his disciplinary authority prior to the impugned transfer was Superintendent of Police, Jaisalmer. May be, as per the stand of the respondents, his seniority will remain as per his seniority in Jaisalmer, but what would happen if the persons junior to him posted in Jaisalmer are promoted, whereas no promotional avenues are available in G.R.P., Ajmer. Will he still be given promotion?

(39) That apart, if due to any delinquency, a disciplinary action is proposed to be taken against the said Constable (Subhash Chandra), whether the Superintendent of Police, Jaisalmer will be the competent authority to initiate the disciplinary proceedings or the Superintendent of Police at Ajmer!

(40) There are many more related or ancillary questions attached with such transfer, such as; at which place the service record of the transferred employees will be kept, who will deal with leave applications etc. of the transferred Constable/Head- Constables and A.S.Is? The Rules of 1989 are silent in this regard. The hiatus, if any, cannot be filled by the administrative orders.

(41) According to this Court, transfers affected by the impugned order, shunting petitioners even out of range, would entail more complications than serving the cause of administration; let alone, the inconvenience caused to the petitioners.

(42) During the course of submission, learned Additional Advocate General apprised the Court that most of the petitioners are facing cases of anti-corruption and hence, in the interest of better administration, the respondent No.2 has decided to transfer these employees out of their respective range, so that they cannot influence the investigation.

(43) This Court feels that the same cannot be a reason or ground to transfer a Constable/Head-Constable or even an A.S.I. out of his range. Such stand reflects State's lack of confidence in the officers and investigating agencies.

(44) As an outcome of the discussion foregoing, these writ petitions deserve to be, and are hereby allowed. The impugned order dated 05.08.2021, qua each of the petitioners, whose names are mentioned in the schedule, including that of Subhash Chandra, is quashed.

(45) The stay application also stand disposed of accordingly.

7. अतः माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया है कि एएसआई पद पर कार्यरत पुलिस कर्मियों का रेंज से बाहर स्थानान्तरण किये जाने के कारण उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। ऐसे में उनका एक रेंज से दूसरी रेंज में पदस्थापन नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग का यह

कथन रहा है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों/अपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसकों विचार में रखते हुए उनकी रेंज परिवर्तित की गयी है।

8. हमारे विचार में आपराधिक प्रकरण विपरीत रूप से प्रभावी नहीं हो, उसके लिये अपीलार्थी का पदस्थापन रेंज में भी किसी भी अन्य स्थान पर किया जा सकता था। इसके अलावा रेंज परिवर्तन किये जाने से अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होना भी स्पष्ट है। अतः हमारे मत में निलम्बन से बहाल किये जाने पर रेंज परिवर्तन किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।
9. परिणामस्वरूप दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण पूर्णराम एवं अनिल कुमार के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 04.08.2023 अपीलार्थीगण की हद तक अपास्त किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थीगण को रेंज में ही किसी भी स्थान पर पदस्थापन करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।
10. उपरोक्त आदेश के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।
11. मूल आदेश अपील संख्या 2123/2023 में एवं छायाप्रति अन्य अपील में सलंग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)